PROF. MADHU DANDAVATE : We are sure we will implement it.

MR. SPEAKER : Why are you interested in Delhi ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, this pertains to Delhi. That is all right. Since the decision is to be taken by the Cabinet, as the Minister has said, there are other regions also in the country. If the decision is to be taken by the Cabinet pertaining to Delhi, will it be extended to other regions because there are lease-holds also around Calcutta and the land-holds by the Central Government ? Are you going to extend to those areas also ?

SHRI BUTA SINGH : At the moment the problem is confined to Delhi and if this works, then it will well be taken by the other States also.

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण

+

*316. श्री राम प्यारे पनिका :
श्री एन० डेनिस :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन शर्तों पर लिया गया है और कितना ऋण लिया गया है ;

(ग) ये सिंचाई परियोजनाएं कौन-सी हैं और उक्त ऋण से ये किन स्थानों पर शुरू की जाएंगी और परियोजनाओं के पूरा होने में सम्भवत: कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(घ) इन परियोजनाओं से कितने किसान लाभान्वित होंगे ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) भारत सरकार विश्व बैंक से 1961 से सिंचाई परियोजना के लिए क्रेडिट तथा ऋण प्राप्त करता रहा है।

(ख) विश्व बैंक से क्रेडिट तथा ऋणों की शर्तें एवं निबंधन उपाबंध-एक में दिए गए अनुसार हैं। 1961 से, भारत सरकार 2669.14 मिलियन अमरीकी डालरों का विश्व बैंक क्रेडिट तथा 240.0 मिलियम अमरीकी डालरों के विश्व बैंक ऋणों को अन्तिम रूप देने में सफल हुई है।

(ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जिन परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, उनके सम्बन्ध में सूचना उपाबंध-दो में दी गई है।

(घ) इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या बता पाना सम्भव नहीं है।

उपाबंध-एक

विश्व बैंक की सहायता दो प्रकार की है। आसान शर्तों पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) से क्रेडिट तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) से विशिष्ट शर्तों पर ऋण। इन दोनों संगठनों को सामान्यत: विश्व बैंक कहा जाता है।

आई० डी० ए० : आई० डी० ए० क्रेडिट दस वर्षों की अनुग्रह अवधि सहित सामान्यत: 50 वर्षों की अवधि के लिए होता है। इसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाता परन्तु क्रेडिट की संवितरित न की गई शेष राशि पर 0.5% प्रति वर्ष का वचनबद्धता शुल्क तथा संवितरित राशि पर 0.75% प्रतिवर्ष का सेवा-प्रभार लिया जाता है।

आई० बी० आर० डी० : आई० बी० आर० डी० ऋण पर बैंक द्वारा प्रत्येक छ: महीने में निर्धारित दर से ब्याज लिया जाता है। ऋण 4

वर्षों की अनुग्रह अवधि सहित 20 वर्षों में अदा करना होता है। इसके अतिरिक्त संवितरित न की गई राशि पर 0.75% प्रति वर्ष वचनबद्धता शुल्क तथा संवितरित की गई राशि पर भी 0.25% प्रति वर्ष अग्र-छोर फीस (फ्रन्ट एन्ड फी) लगाई जाती है।

उपाबंध-दो

राज्य का नाम	परियोजना का नाम/क्रेडिट/ ऋण सं०	एजेंसी	बाह्य सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालरों में)	विश्व बैंक को प्रस्तुत परियोजना के भाग की लागत(मिलियन रुपए में)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1. आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास) (सं० 1251—आई० एन०)	आई०बी० आर०डी०	145.00	2673
गुजरात	1. दूसरी गुजरात सिंचाई (1011—आई०एन०)	आई० डी० ए०	175.00	3024
	2. गुजरात मध्यम-II (रिपीटर)	आई० डी०ए०	172.00	3716
हरियाणा	1. हरियाणा सिंचाई-II परियोजना(1319—आई० एन०)	आई० डी०ए०	150.00	2703.6
कर्नाटक	1. कर्नाटक सिंचाई (788—आई०एन०)	आई० डी०ए०	117.64	2445.4
	2. कर्नाटक टैंक सिंचाई (1116—आई०एन०)	आई०डी०ए०	54.00	650.0
महाराष्ट्र	1. दूसरी महाराष्ट्र सिंचाई (954 आई०एन०)	आई०डी०ए०	210.00	3858.0
	2. महाराष्ट्र जल का उपयोग(सी०आर० 1983—आई०एन०)एल० एन०2308—आई० एन०	आई०डी०ए० आई०बी० आर०डी०	32.00 22.00	741.60

1	2	3	4	5
उड़ीसा	1. महानदी बराज (1078—आई०एन०)	आई०डी०ए०	83.00	926.00
	2. उड़ीसा सोपान-II (1397—आई०एन०)	आई०डी०ए०	105.00	1335.60
पंजाब	1. पंजाब सिंचाई (889—आई०एन०)	आई०डी०ए०	129.00	2215.00
तमिलनाडु	1. पेरियार वैगई सिंचाई II (बातचीत हो गई है।)	आई०डी०ए०		
उत्तर प्रदेश	1. दूसरी यू०पी०, सार्वजनिक नलकूप परियोजना	आई०डी०ए०	101.00	1707.00
	2. ऊपर गंगा का आधुनिकीकरण	आई०डी०ए०	125.00	2498.00
मध्य प्रदेश	1. मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना (1108—आई०एन०)	आई०डी०ए०	140.00	1950.00
	2. मध्य प्रदेश बृहद सिंचाई परियोजना (1177—आई०एन०)	आई०डी०ए०	220.00	3514.40
	3. चम्बल (मध्य प्रदेश) सोपान II परियोजना (1288—आई०एन०)	आई०डी०ए०	31.00	556.40
केरल	1. कल्लाडा सिंचाई और वृक्ष उत्पादन विकास परियोजना			
	(1269—आई०एन०)	आई०डी०ए०	60.00	1365.00
	(2186—आई०एन०)	आई०बी०आर०डी०	20.30	
बहु-राज्य	1. सुवर्णरेखा (बिहार एवं उड़ीसा) सिंचाई परियोजना (1289—आई०एन०)	आई०डी०ए०	127.00	1637.00

SHRI RAM PYARE PANIKA : Sir, Part (d) of my question is : 'the number of farmers to be benefited by these projects'. If it is not possible to give the number of farmers, I want to know how many acres of land have been brought under irrigation by these projects which have been sanctioned by the World Bank.

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह ब्योरा इस समय मेरे पास नहीं हैं कि कितने हैक्टेयर इसमें लाए गए हैं। भारत सरकार विश्व बैंक से 1961 से सिंचाई परियोजनाओं के लिए क्रेडिट तथा ऋण प्राप्त करती रही है। विश्व बैंक से क्रेडिट तथा ऋणों की शर्तें एवं निबंधन उपाबंध-एक में दिए गए अनुसार हैं। 1961 से भारत सरकार 2669.14 मिलियन अमरीकी डालरों का विश्व बैंक क्रेडिट तथा 240.0 मिलियन अमरीकी डालरों के विश्व बैंक ऋणों को अन्तिम रूप देने में सफल हुई है। विश्व-बैंक से सहायता-प्राप्त जिन परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, उनके सम्बन्ध में सूचना उपाबंध-दो में दी गई है। इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या बता पाना सम्भव नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : इन परियोजनाओं के बारे में विभिन्न राज्यों से मुझे यह जानकारी मिली है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद सम्बन्धित राज्यों द्वारा इन परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया जाता है। नतीजा यह है कि लोन की शेष धनराशि को प्राप्त करने में दिक्कत आई है। क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि जो राज्य इस लोन और क्रेडिट को जिन शर्तों पर लें, वे उनके अनुसार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करें ? क्या उनका विचार सैंट्रल स्तर पर इरिगेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इन परियोजनाओं का मानिटरिंग करने का है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : ब्याज की दर 0.5 प्रतिशत है और ऋण की रकम 20 साल में लौटाई जाती है। अगर किसानों को कोई कठिनाई होगी, तो उसको हम देखेंगे।

SHRI N. DENNIS : I would like to know whether foreign experts and World Bank Team visited these projects to provide advisory services. If so, the comments made by them regarding the manner of execution of these works.

SHRI P.C. SETHI : There are no adverse comments.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में आठ सिंचाई परियोजनाएं ऐसी हैं जो पिछले तीस सालों से चालू हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं और उनकी कास्ट दस गुना, बारह गुना बढ़ गई है। उसमें बिहार की कोसी परियोजना भी है, मंत्री जी पीछे बैठे हैं वह सुन रहे हैं, इसी तरह से राजस्थान की भी हैं। तो इस तरीके से आप जो लोन ले रहे हैं या लोन लिया है क्या आपने यह तय किया है या नहीं कि पहले से जो परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं उनको पूरा कर लेंगे तब दूसरी परियोजना को टेक-अप करेंगे या अगर नहीं तो जो 20 साल से चल रही हैं उनकी पूर्ति के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और कितने दिनों में वह पूरी हो जाएंगी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

SHRI K. MAYATHEVAR : There are very noted projects such as Periyar-Vaigai project in my constituency. These have not been completed for the last 25 years. I want to know from the hon. Minister how many projects have not been completed in time and how many projects are incomplete ? Because these have not been completed, the World Bank has refused to give loan for further improvement and official programmes on certain new items.

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : विश्व बैंक ने कभी ऋण देने को मना नहीं किया और मद्रास की परियोजना भी जैसा मैंने कहा, यदि इनकम्पलीट है तो उसको शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जायगा।

SHRI K. MAYATHEVAR : My questions have not been answered. I want your protection.

SHRI P.C. SETHI : Information is not readily available. It will be sent to the hon. Member.

श्री के० के० तिवारी : बिहार में सोन नदी से कुछ नहरें निकलती हैं जो एक सौ साल पुरानी हैं और बिहार के चार जिलों की सिंचाई उन पर निर्भर करती है। उनके आधुनिकीकरण की योजना थी। विश्व बैंक से जो धनराशि मिलती है भारत सरकार को उससे उन नहरों का आधुनिकीकरण किया जाना था। बिहार सरकार से वह पूरी योजना बनकर केन्द्र सरकार के पास आ गई लेकिन केन्द्र सरकार से आज तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली जिसके कारण बिहार की ग्रेनरी कहलाने वाले उन पर चार जिलों में जहां ज्यादा अन्न पैदा होता था, वहां सूखे की स्थिति है और वह चार जिले तबाह हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि विश्व बैंक से जो धनराशि मिल रही है उसमें उसके मुताल्लिक कोई योजना है या नहीं ? यदि है तो उसको पूरा करने में और स्वीकृति देने में इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस परियोजना के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

Purchase of Edible Oils on High Rates by State Trading Corporation

\+

*318. SHRI TRILOK CHAND :
SHRI JAGPAL SINGH :

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether the State Trading Corporation has purchased edible oils from international markets on very high rates which are being distributed throughout the country ; and

(b) if so, whether Government have formulated any guidelines for monitoring imports and distribution by S.T.C. ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) No, Sir. Purchase by State Trading Corporation of various types of edible oils have been at internationally competitive rates.

(b) There is a regular system of monitoring imports and distribution by the Government.

श्री त्रिलोक चन्द्र : मान्यवर, मेरा सवाल बहुत सिम्पल है लेकिन जवाब जिस ढंग से दिया गया है उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि जवाब देने की कोशिश नहीं की गई है। पूछा गया था :

> "क्या राज्य व्यापार निगम से पूरे देश में वितरित किए जा रहे खाद्य तेलों को अन्तर-राष्ट्रीय बाजार से बहुत अधिक मूल्यों पर खरीदा है।"

जवाब मिल गया "नहीं"। हां या नहीं कह देना तो बड़ा आसान है लेकिन कोई रीजन नहीं बताया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है तेल इन्टर-नेशनल मार्केट में ऊंचे दामों पर खरीदे गए। इसका मेन कारण यह है कि एस० टी० सी० एक संस्था है जो खाने का तेल खरीदती है और दूसरी संस्था गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली है, उसको कांट्रैक्ट दिया गया है, वह भी खरीद सकती है। एक तीसरी संस्था है हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम, जो एडियल आयल खरीदती है लेकिन सरकार ने गणेश फ्लोर मिल्स को तो अधिकार दे दिया तेल खरीदने का, फिर हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम को अधिकार क्यों नहीं दिया—यह मैं जानना चाहता हूं। अगर कांपीटिशन था ओपेन मार्केट में तो तीनों संस्थानों को बराबर दिया जाना चाहिए था और कांपिटीशन होना चाहिए था। इसलिए शक पैदा होता है कि एक संस्था को देने का मतलब है कि ओपेन मार्केट से जो माल खरीदा जाता है वह फेयर कांपिटीशन के आधार पर नहीं खरीदा जाता है। यह जानकारी मैं चाहता हूं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी मालूम होती